भारत की अखण्डता के लिए अमर बलिदानी
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के कश्मीर सम्बंधी दिशादर्शक वक्तव्य

अग्नि-पथ

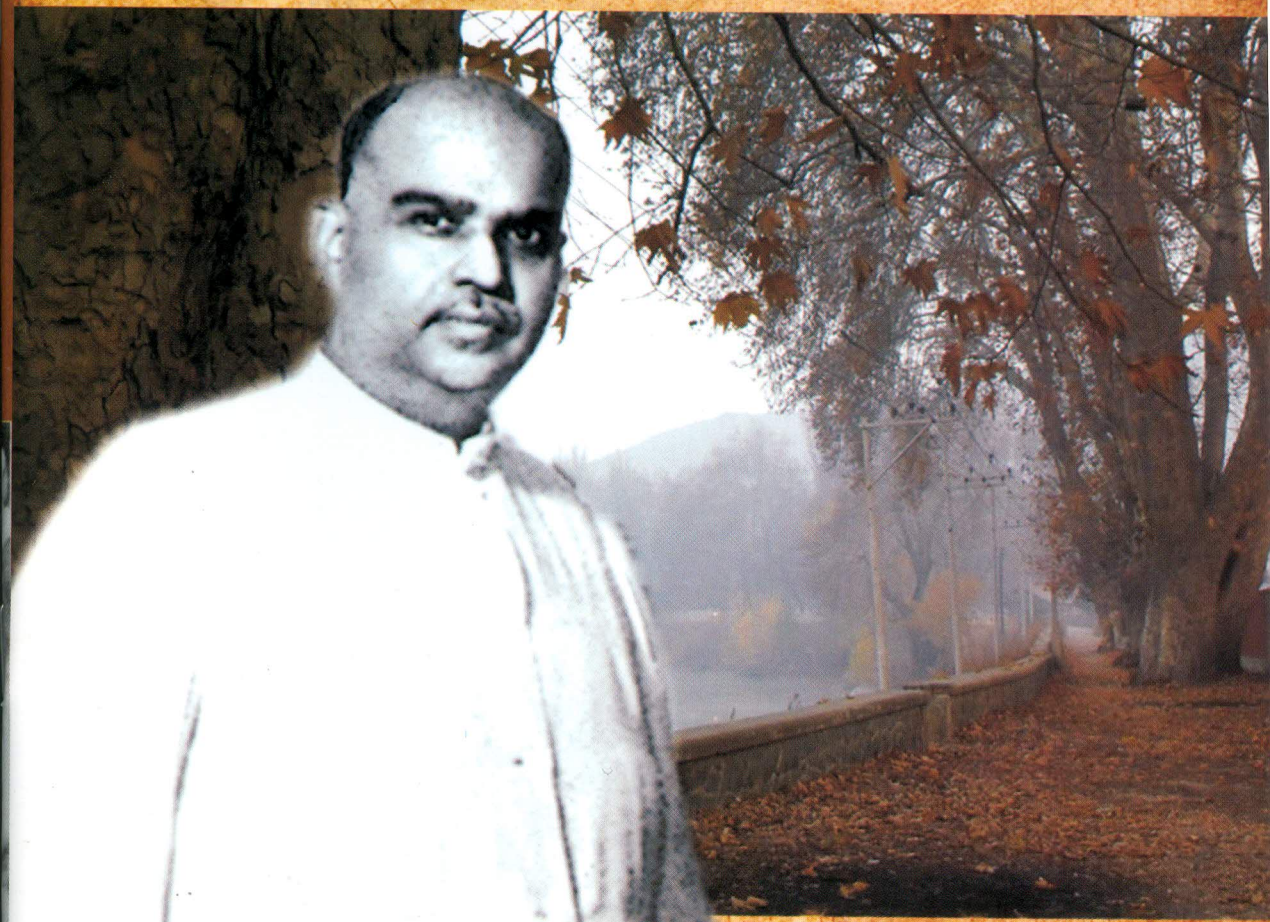

संपादक
तरुण विजय

यह कैसी विडम्बना ?

"कैसी विडम्बना है कि जो देश की अखण्डता बनाये रखना चाहते हैं, वे साम्प्रदायिक बताए जाते हैं। जो मजहब के आधार पर मुसलमानों के लिए देश का विभाजन करने को तैयार हो गए अथवा कश्मीर को स्वतन्त्र मुस्लिम स्टेट बनाने को तैयार हैं, वे नेशनलिस्ट हो गए।"

– डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 8 मई 1953 को पानीपत में।

(पुस्तक : 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जीवनयात्रा, लेखक : शिवकुमार गोयल, पृष्ठ : 94)

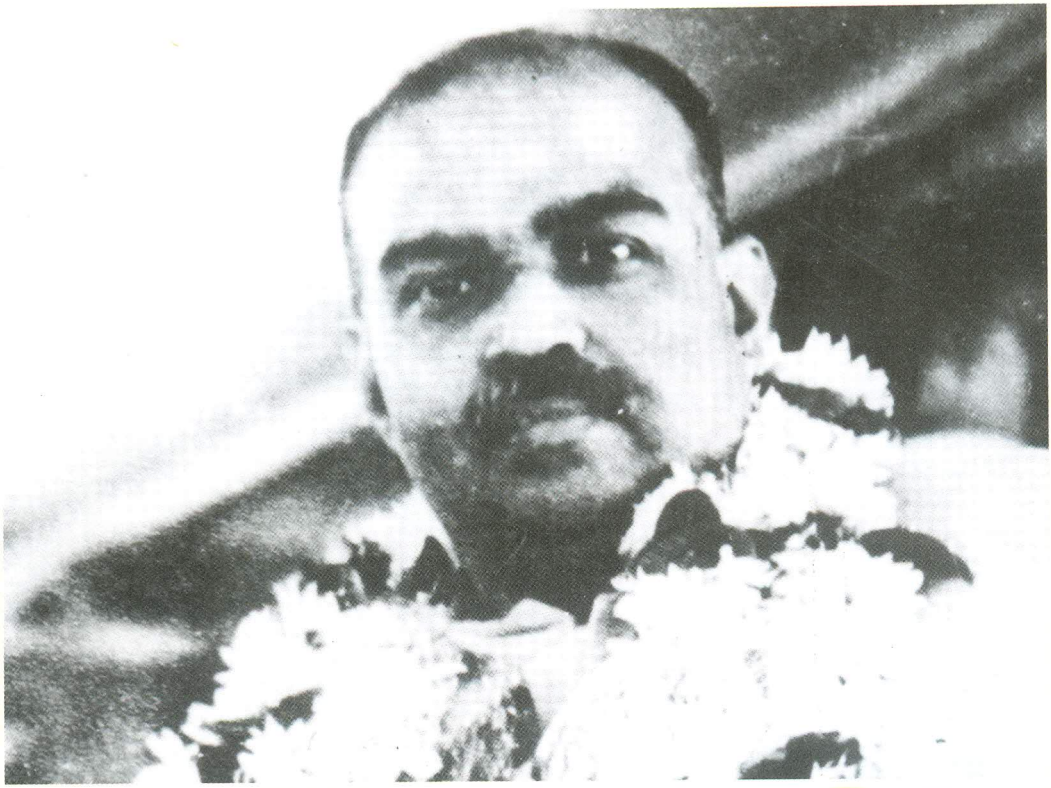

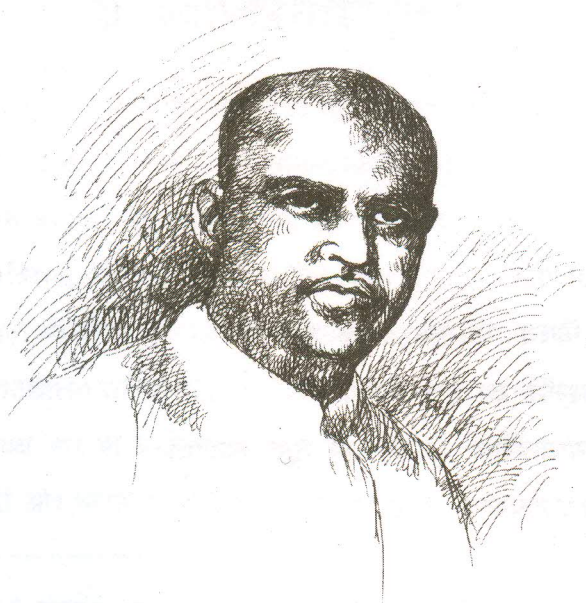

अग्नि-पथ

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी और कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शेष भारत में विलय के बारे में
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के विभिन्न
वक्तव्यों एवं भाषणों के अंश

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान

अनुक्रमणिका

- जीवन परिचय 03
- विचार बिन्दु 05
- श्रद्धा-सुमन 17
- प्रश्न जो अनुत्तरित रहे 20
- संसद में कश्मीर विषय पर ऐतिहासिक भाषण 26
- भारत में जम्मू-कश्मीर का पूर्ण विलय 39
- माधोपुर में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की मूर्ति स्थापित 42
- श्रीनगर में पुनः श्यामाप्रसाद 44

सम्पादक
तरुण विजय

सम्पादन सहयोग
अमरजीत सिंह

आवरण एवं रेखांकन
नरेन्द्र त्यागी

प्रकाशक
डॉ. हर्षवर्द्धन
सचिव, डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी शोध अधिष्ठान
11, अशोक मार्ग, नई दिल्ली–110001

मूल्य : 50/-
प्रकाशन वर्ष : 2011

मुद्रक
नीलकण्ठ कॉम्युनिकेशन
11831/7 प्रथम तल, सत नगर, करोल बाग
नई दिल्ली - 110005

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी (6 जुलाई 1901–23 जून 1953) राष्ट्रीयता के उद्घोषक प्रखर विद्वान् थे। उनका आधुनिक राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में सम्मान किया जाता है। 33 वर्ष की उम्र में सन् 1934 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा उपकुलपति बने और उन्होंने यह दायित्व 1938 तक सँभाला। उन्होंने विश्वविद्यालय में विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और डॉ. एस. राधाकृष्णन् को बंगलोर से कलकत्ता प्राध्यापक के नाते आमन्त्रित किया। उन्होंने लगभग 22 विश्वविद्यालयों (जिनमें मद्रास, बनारस, आगरा और दिल्ली विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं) में दीक्षान्त व्याख्यान दिये। डॉ. मुखर्जी भारत में महाबोधि समाज के संस्थापक अध्यक्ष और श्री अरविन्द के अनुयायी थे। श्रीमाँ आधुनिक भारत के निर्माता के नाते उनका समादर करती थीं और भारतीय राष्ट्रवाद को सशक्त करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका मानती थीं।

महात्मा गाँधी के सुझाव पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें स्वातन्त्र्योत्तर भारत की प्रथम अन्तरिम केन्द्रीय सरकार में उद्योग और आपूर्ति मन्त्री बनाया। उन्होंने सिन्दरी उर्वरक कारखाना, भाखरा नांगल बाँध और भिलाई इस्पात उद्योग को स्वीकृति दी। 6 अप्रैल 1950 को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने 1949 में पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लियाकत अली खाँ से की गई दिल्ली सन्धि के विरोध में मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। वे पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले लाखों हिन्दू शरणार्थियों की शोकान्तिका के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार मानते थे और उन शरणार्थियों पर राज्य सत्ता समर्थित अत्याचार के विरुद्ध प्रबलता से खड़े हुए।

संघ के द्वितीय सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरुजी (श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर) से परामर्श कर डॉ. मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और सर्वसम्मति से उसके पहले अध्यक्ष चुने गए। भारतीय राष्ट्रध्वज की सम्प्रभुता कश्मीर में स्थापित करने के प्रयास में उन्होंने मई 1953 में कश्मीर में बिना परमिट प्रवेश करने की घोषणा की और एक निशान, एक विधान, एक प्रधान की माँग को लेकर कश्मीर में प्रवेश किया। 11 मई 1953 को लखनपुर में शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और श्रीनगर की एक जेल में कारावद्ध रखा। जहाँ 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु की कोई भी जाँच नहीं की गई।

एक गणतन्त्र के भीतर दूसरा गणतन्त्र क्यों ?

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने संविधान सभा में श्री एन. गोपाल स्वामी अयंगर द्वारा अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किए जाने का प्रस्ताव रखने के समय दिए गए भाषण को विस्तार से उद्धृत किया और पूछा –

''कश्मीर का भारत में विलय कैसे होगा ? क्या कश्मीर एक गणतन्त्र के अन्दर दूसरा गणतन्त्र बनने जा रहा है ? क्या हम इस प्रभुत्व-सम्पन्न संसद के अतिरिक्त भारत की सीमा के अन्दर एक और प्रभुत्व-सम्पन्न संसद बनाने की सोच रहे हैं ?''

उन्होंने चेतावनी दी कि '' आप अगर तूफान से खेलना चाहते हैं और यह कहना चाहते हैं कि हम असमर्थ हैं और शेख अब्दुल्ला को अपनी मनमर्जी करने दें, तब कश्मीर को हम खो देंगे। मैं इस बात को जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हम कश्मीर को खो देंगे ।'

–डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 26 जून 1952, लोकसभा में।

(पुस्तक : 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी', मोनोग्राफ सीरीज, पृष्ठ 20, प्रकाशक : लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1990)

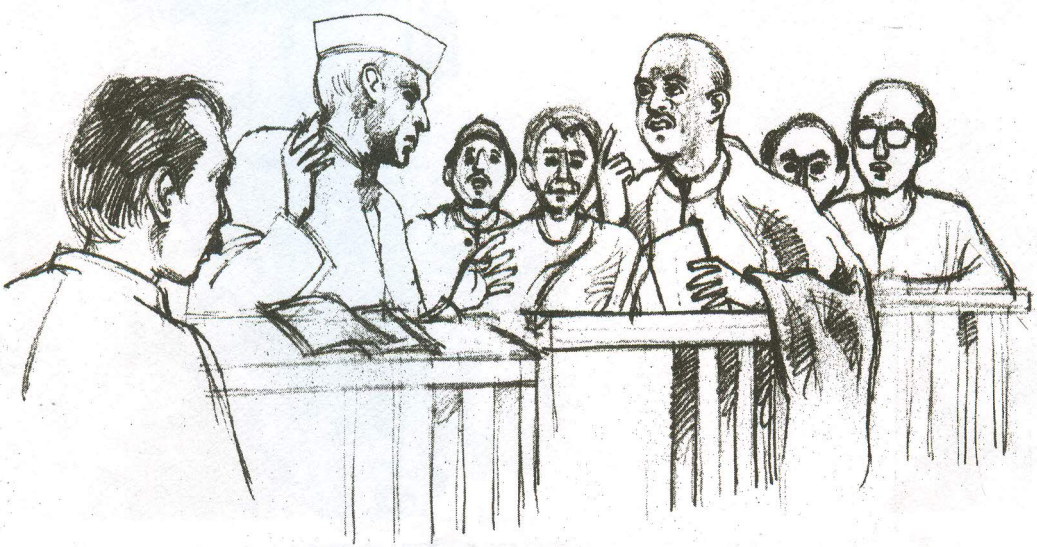

कश्मीरी 'राष्ट्रीयता' क्यों ?

डॉ. मुखर्जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण (26 जून 1952) को एक रचनात्मक सुझाव के साथ समाप्त किया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था।

"प्रधानमन्त्री को साफ-साफ कहना चाहिए कि हम इस प्रकार की कश्मीरी राष्ट्रीयता नहीं चाहते हैं। हम इस प्रभुत्व-सम्पन्न कश्मीर के विचार को नहीं चाहते हैं। अगर आप कश्मीर के बारे में ऐसा करते हैं तो अन्य रियासतें भी ऐसी माँग करेंगी।"

— डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी, 26 जून 1952, लोकसभा में।
(पुस्तक : 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी', मोनोग्राफ सीरीज, पृष्ठ 21, प्रकाशक : लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली, 1990)

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आम चुनावों से सम्बन्धित एक बैठक को सम्बोधित करते हुए : 1952